सूर्य मंदिर की प्रतिकृति हकीकत में तब्दील होगी : मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र

भुवनेश्वर, 16 जुलाई (ए)। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के एक दिन बाद मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र ने आज कहा कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की प्रतिकृति बनाने का उनका सपना अब हकीकत में तब्दील होगा। महापात्र ने यहां लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि कई लोगों ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को असंभव कार्य बताया है लेकिन देश को सूर्य मंदिर देने का कार्य अब जोर पकड़ेगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''मैं कुछ समय से एक नया कोणार्क मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मैं इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के करीब जा रहा हूं।'' उन्होंने कहा कि उनके संसद सदस्य बनने से इस प्रस्तावित परियोजना को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करेंगे। प्रख्यात मूर्तिकार को प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक महत्व के ढांचों के संरक्षण में योगदान देने को लेकर पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किए जाने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार जताया।

कुमारस्वामी ने भावुकता में दिया बयान, गठबंधन में नहीं है तकरार : दानिश अली

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (ए)। जनता दल सेक्यूलर (जेडीएस) ने अपने नेता एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के उस बयान को ''भावुकता में निकला ज्वार'' करार दिया है जिससे राज्य की जेडीएस - कांग्रेस गठबंधन सरकार में दरार के संकेत मिलते हैं। जेडीएस ने कहा कि कुमारस्वामी के बयान का बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। जेडीएस के महासचिव एवं प्रवक्ता दानिश अली ने दावा किया कि कर्नाटक की गठबंधन सरकार पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अली ने बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन साझेदारों के बीच कोई दरार नहीं है और सरकार सुचारू तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा कि वह भावुकता में निकला ज्वार मात्र था और मीडिया में एक तबका इसका बहुत ज्यादा मतलब निकाल रहा है।' अली ने कहा, ''कांग्रेस और जेडीएस के बीच कोई दरार नहीं है। कर्नाटक की गठबंधन सरकार स्थिर है और किसानों , दलितों एवं अन्य वंचित वर्गों सहित राज्य के लोगों के कल्याण के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी।'' गौरतलब है कि कुमारस्वामी ने कल एक कार्यक्रम में जेडीएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री पद पर वह '' खुश नहीं '' हैं और उन्हें भगवान शिव की तरह जहर पीना पड़ रहा है।

पत्नी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, खुद को विस्फोट से बांधकर उड़ाया

जयपुर, 16 जुलाई (ए)। राजस्थान में उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पत्नी के वियोग में एक युवक ने अपने शरीर पर विस्फोटक पदार्थ बांध कर स्वयं को उड़ा दिया। गोवर्धन विलास थानाधिकारी भवानी सिंह राजावात ने बताया कि थाना क्षेत्र के बलीचा गांव के रहने वाले विनोद मीणा का कई दिनों से अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था। इस वजह से उसकी पत्नी अपने पीहर चली गई। विनोद दो तीन दिनों से मानसिक तनाव में था। मृतक पत्थरों की खदान में काम करता था इसलिए खदान में पत्थरों को तोड़ने के लिए काम आने वाले विस्फोटक पदार्थ को अपने शरीर पर बांधकर घर से कुछ दूर सड़क पर आकर उसमें विस्फोट कर आत्महत्या कर ली। विस्फोट के कारण विनोद के शरीर के टुकड़ों में बिखर गया। इस घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शरीर के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गनीमत यह रही कि विनोद ने अपने घर के अंदर इस डेटोनेटर का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आसपास के घरों के अंदर जान और माल का नुकसान हो सकता था।

आंध्र में बाढ़ के कारण फंसे ट्रकों से सुरक्षित निकाले गए 55 लोग

हैदराबाद, 16 जुलाई (ए)। उत्तरी आंध्र प्रदेश में बाढ़ मुसीबत बन चुकी है। सोमवार को इस बाढ़ में फंसे 55 लोगों और उनके पशुओं को जद्दोजहद के बाद बचाया गया। भारी बारिश के कारण श्रीकाकुलम जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। वत्सधारा नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने से जिले में आई बाढ़ में 55 लोगों समेत 10 ट्रक पानी में फंस गए थे। बाढ़ के कारण फंसे ट्रकों में सवार लोग ऊपरी हिस्से पर खड़े हो मदद का इंतजार कर रहे थे। इन्हें बचाने के लिए अधिकारियों ने नावों का सहारा लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, नेवी व फायर डिपार्टमेंट के प्रयासों से इन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। ट्रक में से 20 भेड़ों को भी बचाया गया लेकिन 80 जानवर बाढ़ में बह गए। कर्नाटक से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तमिलनाडु के सलेम जिले में कावेरी के तटों पर रह रहे लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है।

तालिबान के हमले में सात पुलिसकर्मियों की मौत : अफगान अधिकारी

काबुल, 16 जुलाई (ए)। तालिबान लड़ाकों ने पूर्वी नांगरहार प्रांत में पुलिस की एक जांच चौकी पर हमला कर सात पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रांतीय पुलिस प्रमुख गुलाम सनायी स्तानिकजई ने आज बताया कि यह हमला कल रात गनी काहिल जिले में हुआ। जवाबी कार्रवाई में पांच तालिबान लड़ाके भी मारे गए। उन्होंने बताया कि नांगहार प्रांत के खोग्यानी जिले में रविवार रात सरकार की ओर से किए गए एक हवाई हमले में 20 तालिबानी लड़ाके मारे गए। गनी काहिल हमले या हवाई हमले में से किसी पर भी तालिबान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। कल काबुल में एक मंत्रालय परिसर के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था।

पांच यूरोपीय देश फंसे हुए प्रवासियों को देंगे पनाह : इटली के प्रधानमंत्री

रोम, 16 जुलाई (ए)। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते का कहना है कि पांच यूरोपीय देश ईयू की सुरक्षा बलों की दो नौकाओं में सवार 450 में से 250 प्रवासियों को पनाह देने के लिए तैयार हो गए हैं। कोंते ने कल ट्वीट करते हुए कहा, ''स्पेन और पुर्तगाल 50-50 प्रवासियों को पनाह देंगे, फ्रांस, जर्मनी और माल्टा ऐसा पहले ही कर चुके हैं।'' कोंते ने अपने 27 ईयू सहयोगियों से संपर्क कर उन्हें याद दिलाया कि जून के अंत में हुए शिखर सम्मेलन में उन्होंने प्रवासी समस्या को साझा करने की आवश्यकता पर सहमति जतायी थी।

गुमशुदा लड़कियों के बारे में पुलिस को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत : न्यायालय

मुंबई, 16 जुलाई (ए)। पिछले साल ठाणे जिले में गुमशुदा एक लड़की का पता लगाने में पुलिस की नाकामी को गंभीरता से लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस को अपनी मानसिकता बदलने का यह उचित समय है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी औरन्यायमूर्ति भारती डांगरे की सदस्यता वाली एक पीठ ने 10 जुलाई को जारी अपने आदेश में पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्हें यह मानना बंद कर देना चाहिए कि किसी नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का हर मामला उसके अपने प्रेमी के साथ भागने का है, जैसा कि फिल्मों में चित्रित किया जाता है। पीठ ने कहा कि अदालत पुलिस की मौजूदा मानसिकता से नाखुश है। जांच टीमों और उच्चतम ओहदे पर नियुक्त अधिकारियों को हर मामले को ऐसा नहीं मानना चाहिए। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जीवन की वास्तविक घटनाएं हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों की गुमशुदगी की पीड़ा सह रहे हैं और गुमशुदा बच्चे भी कष्ट झेल रहे हैं। अदालत ने कहा, '' यह उचित समय है कि उनकी (पुलिस की) मानसिकता में

बदलाव लाया जाए।'' एक लड़की के पिता की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। उन्होंने इस साल की शुरूआत में यह याचिका दायर कर अपनी बेटी की तलाश के कार्य को तेज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी। अदालत के पिछले निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त सरकारी वकील जेपी याज्ञनिक ने दलील दी कि अब तक की गई जांच के मुताबिक नाबालिग लड़की अपने स्कूल के एक लड़के के बहकाने पर घर छोड़ कर भाग गई थी। वहीं, पीठ ने कहा कि यह मामला एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और उसे उसके माता पिता के संरक्षण से दूर करने का है। बहरहाल, अदालत ने पुलिस को एक ताजा स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए दो हफ्ते का और समय दिया और कहा कि उसे उम्मीद है कि अधिकारियों की सोच में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा।

चांद-सितारे वाले हरे झंडे को बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 16 जुलाई (ए)। चांद सितारे वाले हरे झंडे पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इस पर रोक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस झंडे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टी के झंडे जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वह केंद्र सरकार की राय बताएं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने हरे रंग के चांद-सितारों वाले झंडे को पूरे भारत में बैन करने की मांग की थी। रिजवी ने यह याचिका 17 अप्रैल को दाखिल की थी। रिजवी ने अपनी अपील में कहा है कि हर झंडा जो कई धार्मिक स्थलों पर दिखाई देता है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस झंडे की वजह से अकसर सांप्रदायिक तनाव फैलता है, दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ती है। इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, चांद सितारे वाला हरा झंडा पाकिस्तान और वहां की एक राजनीतिक पार्टी के झंडे से मिलता-जुलता है।

7 दशक के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं लेच पंचायत के लोग

चम्बा, 16 जुलाई (ए)। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत लेच आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाई है। सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीण आज भी रोजमर्रा की वस्तुओं को पीठ पर लादकर ले जाने को मजबूर हैं। आपातकाल में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब मरीज को पालकी में उठाकर उपचार के लिए मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। कई मर्तबा समय पर चिकित्सीय सुविधा न मिलने से मरीज बीच राह में दम तोड़ जाते हैं। ग्रामीणों की सड़क सुविधा से जोडने की मांग पर राजनेताओं की ओर से सिवाय आश्वासनों के कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। इसके अलावा पंचायत को शेष विश्व से जोडने वाले लकड़ी के पुल की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। ग्रामीण हरि सिंह, हरनाम, दिनेश, जगदीश, नरूद व जरमो का कहना है कि लेच पंचायत के लोगों का सड़क सुविधा से जुडने का अभी तक सपना साकार नहीं हो पाया है। सड़क न होने से पंचायत विकास की दौड़ में काफी पिछड़कर रह गई है। उन्होंने बताया कि सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग पर राजनेताओं की ओर से महज आश्वासन ही हासिल हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क न होने से ग्रामीण रोजाना कई किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे हैं। सड़क निर्माण की कवायद महज सर्वे तक ही सिमट कर रह गई है। ग्रामीणों ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिया लाल से मांग की है कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जल्द लेच पंचायत को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए।

भाजपा का सवाल, मुस्लिम की पार्टी वाली अपनी टिप्पणी पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (ए)।। कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहने संबंधी राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने कहा कि विपक्षी पार्टी में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बीमार मानसिकता वाला होने का आरोप लगाए जाने को लेकर भी भाजपा ने पलटवार किया। दरअसल , इससे पहले प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह सिर्फ मुस्लिम पुरूषों के साथ खड़ी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ शर्मनाक आरोप लगाना उनकी हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राहुल ने 'तीन तलाक' पर सरकार की पहल को अब तक अपनी पार्टी का समर्थन नहीं दिया है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने इस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। एक उर्दू अखबार में कांग्रेस को मुस्लिम की पार्टी बताने संबंधी कथित टिप्पणी के लिये राहुल को आड़े हाथ लेते हुए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अब अल्पसंख्यक समुदाय की सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चुनावों के लिए गुजरात गए थे , तब वह जनेऊधारी बन गए थे। उन्होंने कर्नाटक में भी ऐसा ही किया था। अब चुनाव हो गए तो उन्होंने मुसलमानों की सरपरस्ती शुरू कर दी है। प्रसाद ने कहा कि मुद्दा यह है कि राहुल गांधी क्यों संदिग्ध चुप्पी साधे हुए हैं। वह बोल क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने हिलेरी क्लिंटन की मेजबानी के लिए एक दोपहर भोज के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में कहा था कि भगवा आतंकवाद और उग्रवाद लश्कर ए तैयबा से कहीं अधिक खतरनाक है।

मोदी सरकार देश में अघोषित आपातकाल लागू कर रही है : सिंघवी

जयपुर, 16 जुलाई (ए)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि सरकार देश में अघोषित आपातकाल लागू कर रही है। सिंघवी ने यहां एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार हर चीज पर नियंत्रण करना चाहती है और सरकार द्वारा बनाये गये माहौल को इससे पूर्व पहले कभी नहीं देखा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित लोकतंत्र, संविधान, देश बचाने के कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सिंघवी ने कहा कि संविधान का स्तंभ भी खतरे में है।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा एवं निष्पक्षता सर्वोच्च है, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने इसे चौराहे पर ला दिया है। उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ी। उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की चेष्टा को घातक बताते हुए वकीलों से आह्वान किया कि वे सजग भूमिका निभायें। उन्होंने कश्मीर की स्थिति पर कहा कि कश्मीर में शांति प्रक्रिया को भाजपा आगे बढाने में

विफल रही और घाटी में पिछले चार वर्षों के दौरान स्थिति खराब हुई है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पूर्व महासचिव एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस की विरासत को नई पीढ़ी समझे। यह गाँधी और नेहरू का रास्ता है, जिस पर अडिग रहकर देश मजबूत बनाना है, लेकिन भाजपा की विरासत कमजोर है और मोदी सरकार में देश में किसानों, युवाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़े है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट कहा कि आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे है जिनके राज में लोकतंत्र एवं संविधान दोनों खतरे में है। इतिहास में पहली बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सरकार के खिलाफ़ जो कदम उठाया गया था वह इस बात का संकेत है कि सत्ताधारी भाजपा न तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और न ही भारतीय संविधान का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि जिस लोकतंत्र एवं भारतीय संविधान की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है, उसकी अपने ही देश में आज स्थिति यह हो गयी है कि स्वयं भारतीय नागरिकों को लगने लगा है कि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और हारने वालों की भी विपक्ष के रूप में अहम भूमिका होती है लेकिन आज एक ऐसी पार्टी सत्ता में आकर बैठ गयी है, जो खुले आम भारत को विपक्ष मुक्त करने का दावा करती है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इस जनविरोधी भाजपा सरकार को वह उखाड़ फेंकेगी।

चार से पांच सप्ताह में निकल सकता है फॉर्म्युला

सीट बंटवारे पर नीतीश बोले

पटना,16 जुलाई (ए)। बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे का फॉर्म्युला चार से पांच सप्ताह में निकलने के संकेत दिए हैं। नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों के बीच सीट साझा करने का फॉर्म्युला चार से पांच सप्ताह के भीतर आ सकता है। नीतीश पटना में आयोजित लोकसंवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ गत 12 जुलाई को हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर बिहार के सीएम ने कहा कि हमने नाश्ते और रात के खाने पर कई चीजों पर बात की थी। इस दौरान बिहार से जुड़े मुद्दे भी थे। कुमार ने कहा, 'जहां तक प्रश्न लोकसभा चुनाव को लेकर है तो उसके बारे में प्रस्ताव जल्द ही आएगा। यह पूछे जाने पर कि प्रस्ताव आने में कितना समय लगेगा नीतीश ने कहा, सबकुछ एकाध महीने के भीतर होगा। तीन-चार सप्ताह में बाकी सारी बातें होंगी।

बता दें कि बिहार में एनडीए में शामिल दलों में जेडीयू और बीजेपी के अलावा केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की पार्टी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाह का दल आरएलएसपी जैसी छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी साथ मिलकर लड़ी थी, जिनमें बीजेपी को 22 सीटों पर एलजेपी को छह सीटों और आरएलएसपी को तीन सीटें मिली थीं।

पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़ी जेडीयू को सिर्फ दो सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में करारी हार मिलने के बाद जेडीयू ने महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और भारी सफलता हासिल की थी। इससे पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्तीय आयोग में भले ही यह दर्जा नहीं दिया गया हो, आगे इसकी मांग जारी रखी जाएगी।

वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से आयोजित डिनर में उपेंद्र कुशवाहा की गैरमौजूदगी के बाद गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसपर विराम लगाते हुए नितिश ने एनडीए के साथ पार्टी के किसी भी तरह के मनमुटाव की बात को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन्हें चुनाव से पहले ही सुलझा लिया जाएगा।

बादल की गर्ज के बीच विधेयकों को पास कराना होगा सरकार के लिए चुनौती

नई दिल्ली 16 जुलाई (ए)। हंगामे की आशंकाओं के बीच बुधवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार के कई अहम विधेयक आने हैं। इसमें तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड का प्रावधान वाला विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के दौरान हंगामे के चलते इनमें से कई विधेयक लटके रह गए थे, जिन्हें इस बार सरकार पारित कराने की कोशिश करेगी। सूत्रों के अनुसार कुछ अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। तीन तलाक विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। यह विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है। सरकार का जोर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने पर भी है। सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है।

मंच पर केजरीवाल के कदम पड़ते ही गुल हो गयी बिजली

इंदौर, 16 जुलाई (ए)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करने से उस समय नहीं चूके, जब यहां आम आदमी पार्टी (आप) के एक कार्यक्रम के दौरान उनके मंच पर पहुंचते ही बिजली गुल हो गयी। केजरीवाल आप के राज्यस्तरीय पदाधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के सियासी दबदबे वाले परदेशीपुरा इलाके में सम्मेलन स्थल के मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पहुंचने के तुरंत बाद बिजली गुल हो गयी। हालांकि, उस समय केजरीवाल सम्मेलन को संबोधित नहीं कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ देर बाद बिजली आ गयी। इसके बाद केजरीवाल और अन्य वक्ताओं ने बगैर किसी बाधा के अपना संबोधन पूरा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत बिजली गुल होने की घटना से करते हुए कहा, मैंने

सुना तो था कि मध्यप्रदेश में बिजली की हालत काफी खराब है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि दूसरे राज्य के किसी मुख्यमंत्री के मध्यप्रदेश दौरे में ठीक उसी समय बिजली चली जाती है, जब वह पंडाल में पहुंचा ही हो। उन्होंने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ हुई इस घटना से समझा जा सकता है कि बिजली आपूर्ति के मामले में सूबे के आम आदमी पर क्या बीतती होगी।

ब्रिटिश सरकार खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन पर नहीं लगाएगी बैन

लंदन, 16 जुलाई (ए)। भारतीय प्राधिकारी द्वारा ब्रिटेन सरकार को लिखे एक पत्र के बाद ब्रिटेन के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि खालिस्तान समर्थन वाले एक ब्रिटेन सरकार की खालिस्तान समर्थन वाले प्रदर्शन पर बैन लगाने की तब तक कोई योजना नहीं है जब तक यह कानून के दायरे में रहता है और हिंसा में संलिप्त नहीं होता है। भारतीय प्राधिकारियों ने पत्र में कहा था कि ब्रटेन सरकार सिख फॉर जस्टिस समूह ने 12 अगस्त को ट्रेफेलगर स्क्वायर पर एक रैली के आयोजन के विरोध में कदम उठाएं।

इस रैली का मकसद खालिस्तान के लिए संप्रभु देश की मांग करना है और इसका नाम लंदन

डिक्लरेशन (लंदन घोषणा) रखा गया है, जिसमें 2020 रेफरेंडम (जनमत संग्रह) की बात कही गई है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में ब्रिटेन, यूरोप और अमरीका के सिख हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, ब्रिटेन में लोगों को एकजुट होने और अपने विचारों के प्रदर्शन का अधिकार है। अगर वह कानून के तहत अपनी बात रखते हैं तो उन्हें यह अधिकार है. भारत के विदेश मंत्रालय के बयान जारी करने के बाद यह प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हम आशा करते हैं कि ब्रिटेन सरकार इस तरह के किसी भी समूह को जो घृणा फैलाती हो और जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंध पर असर पड़ता हो, उसे अपने देश का इस्तेमाल नहीं करने देगी। वहीं रैली का आयोजन करने वाले इस समूह ने अपने बयान में कहा है, लंदन डिक्लेरेशन एक शांतिपूर्ण अभियान है जो सिखों के आत्म निर्णय के अधिकार (जिसकी गारंटी संयुक्त राष्ट्र चार्टर और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है) के लिए गैर बाध्यकारी जनमत संग्रह है।